भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी)
दण्डकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी

प्रेस वक्तव्य

दिनांक–25 मार्च, 2019

झूठे लोकसभा चुनावों के बहिष्कार का आह्वान!

लोकसभा चुनावों की नौटंकी जोर पकड़ी है. लोगों को दिग्भ्रमित करने, लुभाने व भटकाने के जरिए वोट एवं सीट पाने भाजपा, कांग्रेस समेत सभी संसदीय दलों ने अपनी–अपनी कवायदें तेज की हैं. हमारे देश का संसदीय जनवाद झूठा है. साम्राज्यवादियों के बीच एवं देश के दलाल नौकरशाही पूंजीपति और बड़े सामंती वर्गों का प्रतिनिधित्व करने वाली विभिन्न राजनीतिक पार्टियों (शासकीय गुटों) के बीच प्रतिस्पर्धा की अभिव्यक्ति के तौर होने वाले इन धोखेबाजीपूर्ण और कपटतापूर्ण चुनावों का मुख्य उद्देश्य यह तय करना कि किस शासकीय गुट सत्तासीन होकर और पांच सालों तक साम्राज्यवादियों और देश के शोषक वर्गों के हित पूरा करने के लिए व्यापक जनसमुदायों पर अपना क्रूर शासन जारी रखेगा. यह स्पष्ट है कि ''संसदीय रूप, नकाब पहने बुर्जुआ वर्ग की तानाशाही ही है'' और ''आधुनिक राज्य की कार्यपालिका पूरे बुर्जुआ वर्ग के सामान्य मामलों का संचालन करनेवाली समिति के अलावा और कुछ नहीं है''.

दरअसल वर्तमान में हमारे देश में नए औपनिवेशिक रूप के साम्राज्यवादी परोक्ष शासन, शोषण और नियंत्रण के तहत अर्ध औपनिवेशिक और अर्ध सामंती व्यवस्था अस्तित्व में है.

यह सभी को ज्ञात है कि 2014 में हुए संसदीय चुनावों में – कांग्रेस नेतृत्व वाली संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन(यूपीए)–2 की सरकार के प्रति जनता में व्याप्त असंतोष, आक्रोश और विरोध का इस्तेमाल कर, साम्राज्यवादियों और देश–विदेशी कार्पोरेट अरबपतियों के बलबूते, सस्ती लोकप्रियता के वादों, जुमलों व दिग्भ्रांतिपूर्ण प्रचार के साथ, जनता के बीच भ्रम फैलाकर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) सत्तासीन हुआ.

भाजपा ने साम्राज्यवादी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के हितों को पूरा करने के लिए अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आइएमएफ), विश्व बैंक, विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्युटीओ) के आदेशों के अनुसार, कांग्रेस नेतृत्व वाली यूपीए–2 द्वारा लागू नयी उदारवादी नीतियों का ही अनुसरण करते हुए उन्हीं नीतियों को और गति दी है. उसने किसी भी चुनावी वादे को पूरा नहीं किया, बल्कि जनता पर शोषण और उत्पीड़न को और तेज किया है. मोदी सरकार की नीतियों के कारण रुपये का मूल्य डालर के मुकाबले 73 रुपये तक पहुंच गया है. औद्योगिक और कृषि संकट गंभीर स्तर तक पहुंच गया है. तैयारी (मानुफक्चरिंग) उद्योग रोज–रोज कमजोर हो रहा है. देश का व्यापार घाटा लगातार बढ़ता गया. देश में भ्रष्टाचार, गरीबी, आवासहीनता, बेरोजगारी, अशिक्षा, साफ पेयजल का अभाव, अस्वस्थता, महंगाई बड़े पैमाने पर बढ़ गयी हैं. इस कारण लाखों की तादाद में लोग रोजी रोटी के लिए विदेशों, शहरों या दूसरे राज्यों में पलायन कर रहे हैं, जहां वे अकथनीय शोषण, उत्पीड़न और अत्याचारों का शिकार हो रहे हैं. भुखमरी और आत्महत्याएं बढ़ रही हैं. नोटबंदी और जीएसटी ने गरीबों, मंझोले वर्ग के लोगों, युवाओं व छोटे दुकानदारों की कमर तोड़ दी है.

कुल मिलाकर कहा जाए तो मोदी के अच्छे दिन अंबानी, अदानी आदि के लिए हैं जबकि आम आदमी को सबसे बुरे दिन झेलने पड़ रहे हैं. प्रत्येक व्यक्ति के खाते में 15 लाख रुपए डालने की बात तो कोसों दूर, अभी सभी के खातों की रकम को पूंजीपतियों के लिए लुटाया जा रहा है और खातों में विदेशी कर्ज चढ़ाया गया है. पूंजीपतियों के लिए लाखों करोडों की कर्ज माफी, किसानों के लिए आत्महत्याएं. सरकार की जन विरोधी व देशद्रोही नीतियों के खिलाफ आवाज उठाने वाले देशद्रोही करार दिए गए, सलाखों के पीछे डाल दिए गए एवं मरवाए गए. नया भारत के नाम पर ब्राह्मणीय हिंदुत्व फासीवादी भारत का निर्माण करने पर तुली हुई है. गोरक्षा के नाम पर दलितों, मुसलमानों व आदिवासियों की सरे राह गोगुंडों द्वारा हत्याएं की जा रही हैं.

मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्मार्ट सिटीज, बुलेट ट्रेन, स्किल इंडिया, स्टार्ट अप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया आदि कई लोकलुभावन योजनाओं, जुमलों, कोरी लफ्फाजी, अनर्गल बातों के जरिए विकास का बहाना करते हुए लोगों को दिग्भ्रमित कर देशी, विदेशी कॉरपोरेट घरानों की सेवा व गुलामी व उनकी संपत्ति एवं लूट का चौकीदार बना हुआ है, देश के प्रधान मंत्री पद पर बैठा नरेंद्र मोदी. देश के अंदर रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल

इंटिलिजेंस, क्लाउड कंप्यूटिंग जैसे नयी प्रौद्योगिकी (टेकनोलोजी) घुसने के कारण भी नौकरियों में कमी आई है. ठेका मजदूर व्यवस्था और आउटसोर्सिंग में बढ़ोत्तरी हुई है. तमाम जन कल्याणकारी योजनाओं से हाथ खींचने नयी व धोखेबाजीपूर्ण नीतियों की घोषणाएं कर रहा है. बजट में निधियों के आवंटन में लगातार कटौती कर रहा है. भ्रष्टाचार व घोटालों का अंबार लगा है.

मोदी देश भर में उठ रहे विरोध को भांपते हुए आगामी चुनावों में दोबारा सत्ता दखल करने की गलत नीयत से पड़ोसी देश पाकिस्तान से तनावपूर्ण व जंग का माहौल बनाकर पाक विरोधी उन्माद व्याप्त कर अपना उल्लू सीधा करने भरसक कोशिश कर रहा है. लेकिन शोषण व उत्पीड़न के विरोध में एवं अपनी तबकाई समस्याओं को लेकर विभिन्न उत्पीड़ित वर्गों व तबकों की जनता एवं अपनी अस्मिता, अस्तित्व व आत्मसम्मान एवं अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए, ब्राह्मणीय हिंदुत्व धर्मोन्माद के विरोध में दलित, आदिवासी, मुसलमान व ईसाई समेत अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक, पिछड़े वर्गों के लोग लगातार सड़कों पर बड़े पैमाने पर उतर रहे हैं. विशेषकर पांचवीं अनुसूची वाले इलाकों के आदिवासी अवाम पेसा कानून के तहत ग्राम सभाओं के अधिकारों के लिए जोरदार संघर्ष कर रहा है जोकि उत्तर छत्तीसगढ़ में पत्थलगड़ी आंदोलन के नाम से प्रचलित हुआ.

देशी, विदेशी कॉरपोरेट लूट को बेरोकटोक जारी रखने, उसके लिए आवश्यक बड़ी खनन, भारी औद्योगिक, बांध परियोजनाओं को जबरन व जन विरोध को दबाकर शुरु कराने दंडकारण्य समेत संसाधन बहुल वन इलाकों जोकि सशस्त्र संघर्ष के इलाकें भी हैं, में लगातार पुलिस व अर्ध सैनिक बलों की तैनाती को बड़े पैमाने पर बढ़ाते हुए जन दमन की पाशविक योजना समाधान पर बर्बर तरीके से अमल किया जा रहा था. छत्तीसगढ़ में अपने 15 वर्षीय कार्यकाल में भाजपा सरकार ने गोंपाड, सिंगारम, ताकिलोड, सार्किनगुडा, एड्समेट्टा, नुल्कातोंग आदि नरसंहारों को अंजाम दिया.

भीमा कोरेगांव के 200वें वार्षिक स्मृति दिवस के अवसर हुए जनप्रदर्शन को बर्दास्त नहीं करने वाले हिंदू फासीवादी तत्वों ने उस पर महाराष्ट्र राज्य सरकार के बल पर पाशविक रूप से हमलें किए हैं. इन अपराधियों पर कोई कार्रवाही नहीं की गई. इस के विपरीत मोदी की हत्या करने की साजिश का बहाना बनाकर देशभर में दलित, जनवादी और सामाजिक कार्यकर्ताओं पर मोदी के भाड़े के पुलिस बलों द्वारा यूएपीए जैसे क्रूर कानून लगाकर उन्हें जेलों में ठूंसकर, देश में आतंक मचाया गया. केंद्र की तर्ज पर महाराष्ट्र में फडणवीस सरकार भी राज्य के संसाधनों को देशी, विदेशी पूंजीपतियों के हवाले कर रही है और दूसरी ओर कल्लेडा, हल्बी–तुम्मीरगुंडा जैसी मुठभेड़ों, झूठी मुठभेड़ों को अंजाम देते हुए संघर्षरत पार्टी, पीएलजीए व जनता पर पाशविक दमन जारी रखी हुई है.

अब कांग्रेस पार्टी के बारे में देखे, तो उसने देश में तथाकथित आजादी के बाद से सबसे ज्यादा समय तक सत्ता की बागडोर संभाल रखी थी और वह जन विरोधी, देश द्रोही व जन दमनकारी नीतियों पर अमल करती रही. कश्मीर, उत्तरपूर्व के आंदोलनों समेत तेलंगाना, नक्सलबाड़ी व श्रीकाकुलम के किसान सशस्त्र आंदोलनों को खून की नदी में डुबोने का इतिहास रहा है, कांग्रेस का. 1984 के सिख्कों के कत्लेआम सहित कांग्रेस/यूपीए के शासन में मुस्लिमों, दलितों, आदिवासियों, महिलाओं पर अत्याचार और हत्याकांडों को अंजाम दिया गया. आज देश में किसानों की आत्महत्याओं का जो सिलसिला जारी है वह कांग्रेस पार्टी द्वारा देश में लायी गई नयी उदारवादी नीतियों की देन है. अपना अपराध पर नकाब डालते हुए आज किसानों की कर्ज माफी की बात कांग्रेस कर रही है. वह कुछेक संसदीय पार्टियों के साथ महागठबंधन बनाकर चुनावों में बहुमत प्राप्त करने का सपना देख रही है.

15 साल के लंबे अंतराल के बाद छत्तीसगढ़ में सत्तारूढ़ कांग्रेस सरकार अपनी पूर्ववर्ती भाजपा की तमाम जन विरोधी व कॉरपोरेटपरस्त एवं जन दमनकारी नीतियों पर बेरोकटोक अमल कर रही है. इंद्रावती एरिया के ताडिबल्ला में नरसंहार को अंजाम देते हुए 10 मिलिशिया व जनता को मौत के घाट उतार दिया गया. सुकमा जिला, गोडेलगुड़ा गांव की महिलाओं पर अंधाधुंध गोलीबारी कर सुक्की पोडियाम की हत्या की गई.

अब बाकी पार्टियों के बारे में देखा जाये तो, देश में नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी के साथ–साथ, पंजाब में अकाली दल, महाराष्ट्र में शिवसेना, आंध्रप्रदेश और तेलंगाना में तेलुगु देशम और वाइ.एस.आर. कांग्रेस, तेलंगाना में टीआरएस, तमिलनाडु में डीएमके और एआईडीएमके, हरियाणा, उत्तरप्रदेश, बिहार, ओड़िशा और कर्नाटक में अलग–अलग पार्टियों और ग्रुपों के रूप में मौजूद जनतादल, पश्चिम बंगाल में तृणमुल कांग्रेस पार्टी, कश्मीर में नेशनल कान्फरेंस, पीपुल्स डेमोक्रटिक पार्टी, असम में असम गण परिषद, मिजोराम में मिजो नेशनल फ्रंट, छत्तीसगढ़ में जनता कांग्रेस आदि पार्टियां मुख्य रूप में साम्राज्यवाद की ही दासता करते हुए, दलाल नौकरशाही बुर्जुआ और बड़े सामंती वर्गों का प्रतिनिधित्व करने वाली पार्टियां ही हैं. इनमें से अधिकतर पार्टियां विभिन्न राज्यों में राष्ट्रीयता आकांक्षाओं का, दलित, बहुजन लोगों की मुक्ति की आकांक्षाओं का इस्तेमाल करते हुए अपना समय काट रही हैं. इनके अलावा, भाकपा (मार्क्सवादी) और भाकपा जैसी संशोधनवादी पार्टियां उत्पीड़ित जनता और तबकों के आंदोलनों को क्रांति के रास्ते से भटकाने का काम कर रही हैं. इसमें

भाकपा (मार्क्सवादी) ने पश्चिम बंगाल, केरल और त्रिपुरा जैसे राज्यों में जब सत्ता में होती है, तब जनांदोलनों को कुचलने में लगी रहती है, जब विपक्ष में होती है, तब राजनीतिक रूप से जनता के पक्ष लेने में अवसरवादी रुख अपनाती है. यह हमारी पार्टी के नेतृत्व में जारी क्रांतिकारी आंदोलन को कुचलने में मुख्य पार्टियों के साथ होड़ में लगी हुई है. ये सभी पार्टियां साम्राज्यवाद और लुटेरे वर्ग हितों की रक्षा करते हुए प्रतिक्रियावादी भूमिका निभा रही हैं.

हमारा देश के अर्धऔपनिवेशिक और अर्धसामंती लुटेरी व्यवस्था के स्थान पर सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक समानता व मानवता–युक्त समाज अपने आप उभरकर आना संभव नहीं है. देश की पूरी संपदाओं को जिस तरह इस देश के लोग पैदा कर रहे हैं, उसी तरह शोषण और उत्पीड़नविहीन समाज को भी अपने आत्मगत प्रयास के जरिए उत्पीड़ित वर्गो व तबकों की जनता को ही निर्मित करना होगा. इस महान कार्य को कोई भी राजनीतिक पार्टी कार्यान्वित कर सकती है, इसके लिए इंतजार करना सिर्फ भ्रम ही होगा. आइए! झूठे चुनावों का बहिष्कार कर, हमारे देश में मौजूदा लुटेरी व्यवस्था जो दलाल नौकरशाह पूंजीपति और बड़े सामंत वर्गों और उनके साम्राज्यवादी मालिकों का प्रतिनिधित्व करती है, को उखाड़ फेंककर उसकी जगह में सच्ची जनवाद और स्वावलंबन की बुनियाद पर भारत की जनता के जनवादी गणतंत्रों के संघ के निर्माण के लिए, जोतने वालों को जमीन के नारे पर आधारित होकर, कृषि क्रांति की धुरी पर, नवजनवादी क्रांति को सफल बनाने के लक्ष्य से, सर्वहारा के नेतृत्व में, मजदूर–किसान की मित्रता के आधार पर मजदूर, किसान, निम्नपूंजीपति वर्ग, देशीय बुर्जुआ वर्गों के साथ क्रांतिकारी संयुक्त मोर्चा के नेतृत्व में जारी दीर्घकालीन लोकयुद्ध में सक्रिय रूप से हिस्सा लें. जनता की समस्याओं के हल के लिए चुनाव नहीं, बल्कि संघर्ष ही एक–मात्र रास्ता है. देशभर में जनता की क्रांतिकारी राजसत्ता को स्थापित कर, दीर्घकालीन लोकयुद्ध को अंतिम जीत की तरफ आगे बढ़ाना ही जनमुक्ति का रास्ता है.

इसी रास्ते पर दंडकारण्य की संघर्षरत जनता आगे बढ़ रही है. दंडकारण्य में शोषक–शासक वर्गों को उखाड़ फेंक कर क्रांतिकारी जनताना सरकारों, जिनके द्वारा यहां की जनता के आर्थिक स्वावलंबन व असली विकास को हासिल करने, राजनीतिक चेतना बढ़ाने, अस्मिता व आत्मसम्मान को बचाने, संस्कृति को विकसित करने, प्राकृतिक संपदाओं व संसाधनों को बचाने की कोशिश जारी है, का निर्माण व उनका विस्तार करने का प्रयास जनयुद्ध व जन संघर्ष के जरिए कर रही है. इसी सिलसिले में हर लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय चुनावों का बहिष्कार कर रही है. ठीक इसी तरह इस बार भी लोकसभा चुनावों का बहिष्कार करें और क्रांतिकारी जनताना सरकारों का निर्माण और उनका विस्तार करने में आगे बढ़ें.

विकल्प

(विकल्प)
प्रवक्ता
दण्डकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी
भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी)